साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 41 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 31 मई 2023 से 6 जून 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

मिशन लाइफ को केंद्र में रखते हुए मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2023

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) एक ऐसा अवसर है जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता और क्रियाशीलता के लिए देश भर के लाखों लोगों को एकजुट करता है। इस वर्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने मिशन लाइफ को केंद्र में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाने की परिकल्पना की है। लाइफ का अर्थ है- पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जिसकी शुरुआत 2021 यूएनएफसीसीसी कॉप-26 के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में आयोजित वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में की थी. तब उन्होंने स्थायी जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक लक्ष्य को फिर से हासिल करने का आह्वान किया। समारोह के उपलक्ष्य में लाईफ पर देश भर में जन भागीदारी का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के सहयोग से राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ने लोगों के बीच व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए मिशन लाइफ ऑन वेस्ट रिड्यूस्ड (स्वच्छता से संबंधित कार्य) के लिए जन भागीदारी को शुरू किया गया, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गाजियाबाद की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मीनाक्षी करावल ने एक पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने लाइफ क्रियाओं को अपनाने का भी संकल्प लिया।

एनएमएनएच के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए कार्यक्रम- आरएमएनएच, मैसूर-एनएमएनएच-एमओईएफसीसी ने छात्रों और आम जनता के लिए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के तहत 05.05.2023 को मास्क बनाने की गतिविधि का आयोजन किया और हरित प्रतिज्ञा के साथ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आरजीआरएमएनएन, सवाई माधोपुर ने मिशन लाइफ, जल प्रदूषण पर हरित चर्चा (ग्रीन टॉक), जल बचाओ (सेव वॉटर), समुद्री इको सिस्टम का महत्व और जलवायु परिवर्तन पर एक ओरिएंटेशन का आयोजन किया। आज लगभग 478 छात्रों, आगंतुकों और आम जनता ने पानी बचाओ, समुद्री इको सिस्टम- महासागरीय जीवन, जलवायु परिवर्तन- मजेदार तरीके से सीखें और फिल्म शो तथा सेल्फी कॉर्नर का आनंद लिया।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने युवाओं में जागरूकता लाने के लिए %सेव वॉटर (पानी बचाओ)% और %से नो टू प्लास्टिक (प्लास्टिक को ना)% पर मिशन लाइफ के लिए जन भागीदारी शुरू की, जिसमें डॉ. धृति बनर्जी, निदेशक, जेडएसआई ने वर्चुअल माध्यम से वहां मौजूद लगभग 100 युवाओं और उत्साही युवा प्रतिभागियों से बातचीत की।

राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) चेन्नई ने आज सिग्नेचर कैंपेन और ग्रीन प्लेज के माध्यम से लाइफ प्रथाओं के मिशन लाइफ के लिए जन भागीदारी की शुरुआत की। यह कार्यक्रम तटीय, कृषि और शहरी लचीलेपन और प्रारंभिक चेतावनी के हाइड्रोमेट सर्विस पर विश्व बैंक की कार्यशाला का एक हिस्सा था, जिसका उद्देश्य तटीय इलाकों में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेना है. इस कार्यशाला में, बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया और तटीय प्रबंधन एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को लेकर अपने अनुभव साझा किए। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, एनसीएससीएम के निदेशक पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थायी जीवन शैली की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान प्रोफेसर वी. गीतालक्ष्मी, कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, प्रो. सुनील कुमार सिंह, निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा, डॉ. एस. बालचंद्रन, वैज्ञानिक-जी, प्रमुख, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, चेन्नई, एमओईएस, डॉ एनी जॉर्ज, बीईडीआरओसी, केरल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने हरित शपथ और गंदगी के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान तथा प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने की आवश्यकता पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

जल जीवन मिशन से ग्रामीण महिलाओं की गरिमा एवं प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि

भोपाल प्रदेश में जल जीवन मिशन के लाखों हितग्राही में देवास ज़िले के ग्राम सुकल्या क्षिप्रा के रहवासी भी शामिल हो गये हैं। ग्राम में 1378 परिवार की 5128 जनसंख्या निवास करती है। पहले ग्राम में पानी की समस्या थी। ग्रामीणजन क्षिप्रा नदी से पेयजल लाने के लिये मजबूर थे। ग्रीष्म ऋतु में तो पेयजल व्यवस्था बड़ी चुनौती थी। अब ग्राम में 1 करोड़ 61 लाख की लागत से उच्च स्तरीय टंकी एवं 6400 मीटर पानी वितरण नेटवर्क का निर्माण किया गया है। स्वच्छ एवं शुद्ध जल के लिए कीटाणु शोधक यंत्र भी लगाया गया है। आज सभी 1378 घरों को नियमित, भरपूर एवं शुद्ध पेयजल मिल रहा है। संरपच श्री विश्वास उपाध्याय ने बताया कि पहले पेयजल की व्यवस्था पंचायत द्वारा नलकूप खनन कर की जाती थी, जिसके नियमित संचालन में परेशानियाँ थी। जल जीवन मिशन से ग्रामीणजन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हुई है। सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिये ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति गठित है, जो योजना की सतत निगरानी करती है। योजना का संचालन संजना स्व-सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। संजना स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा जल कर वसूली एवं हिसाब रखने का कार्य किया जा रहा है। इससे समूह के सदस्यों को आर्थिक फायदा भी मिल रहा है। समूह रख-रखाव एवं पानी के बचाव को लेकर ग्रामवासियों को जागरूक भी करता है। अब ग्राम में हर घर में 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन नल जल की उपलब्धता है।

प्लास्टिक मुक्त दुनियाः रीसाइक्लिंग से बढ़ जाती है प्लास्टिक में विषाक्तता, ग्रीनपीस ने अध्ययन में दी चेतावनी

शिमला। रीसाइक्लिंग, प्लास्टिक प्रदूषण का रामबाण इलाज नहीं है। इसपर किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि पुनर्चक्रण की यह प्रक्रिया वास्तव में प्लास्टिक की विषाक्तता को बढ़ाती है। यह जानकारी ग्रीनपीस द्वारा जारी नई रिपोर्ट ॅरएवर टॉक्सिकञ्द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रीसाइक्लिंग में सामने आई है। इस रिपोर्ट को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पेरिस में हो रही अंतर सरकारी वार्ता समिति के दूसरे सत्र से पहले जारी किया गया है।

यह वार्ता 29 मई से 2 जून, 2023 के बीच हो रही है, जिसका लक्ष्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए वैश्विक स्तर सभी देशों को एकजुट करना और उनके बीच वैश्विक संधि करना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से सर्कुलर इकॉनमी के लिए असंगत हैं, यह दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि पेरिस में प्लास्टिक संधि को लेकर चल रही वार्ता में प्लास्टिक उत्पादन को सीमित और कम करने के प्रयास करने चाहिए। देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोकेमिकल और रोजमर्रा की चीजे बनाने वाली कंपनियां जैसे नेस्ले, यूनिलीवर और कोका-कोला के साथ-साथ प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए समाधान के रूप में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पर जोर दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह सही नहीं है।

रिपोर्ट में जो तथ्य सामने हैं उनके मुताबिक प्लास्टिक में 13,000 से अधिक केमिकल्स होते हैं जिनमें से 3,200 इंसानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इस बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि अक्सर रीसायकल प्लास्टिक में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। साथ ही वो पारिस्थितिक तंत्र को दूषित कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में उन तीन तरीकों की पहचान की है, जिसमें पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री हानिकारक रसायनों को अपने अंदर संजो सकती हैं इसमें सबसे पहले नए प्लास्टिक में मौजूद जहरीले केमिकल्स से सीधे तौर पर होने वाला प्रदूषण शामिल है। इसी तरह प्लास्टिक कंटेनरों में भरे कीटनाशक, सफाई करने वाले सॉल्वैंट्स और अन्य पदार्थ जो रीसाइक्लिंग चेन में प्रवेश कर रहे हैं वो प्लास्टिक को दूषित कर सकते हैं। इसी तरह पुनर्चक्रण प्रक्रिया, जिसमें प्लास्टिक को गर्म किया जाता है वो भी इसमें हानिकारक केमिकल्स को बढ़ा सकते हैं। अक्सर प्लास्टिक उत्पादन, निपटान और उनको भस्म करने की सुविधाएं, दुनिया के कमजोर, पिछड़े समुदायों के आसपास स्थित होती हैं। ऐसे में इनसे निकलने वाले हानिकारक केमिकल्स के संपर्क में आने से उनमें कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है।

रीसाइक्लिंग दुर्घटनाओं से भी है स्वास्थ्य को खतरा रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते प्लास्टिक के साथ-साथ, रीसाइक्लिंग सुविधाओं में भीषण आग का खतरा भी बढ़ गया है, खासकर उन जगहों पर जहां इस्तेमाल की गई बैटरी के साथ ई-कचरा के रूप में प्लास्टिक भी होता है। 2022 में अमेरिका और कनाडा में किए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट सुविधाओं में आग लगने के रिकॉर्ड 390 मामले दर्ज किए गए थे। तुर्की की एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उस देश में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं में आग लगने की घटनाएं 2019 में 33 से बढ़कर 2021 में 121 हो गई हैं। इसी तरह अप्रैल 2023 तक पिछले 12 महीनों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, रूस, दक्षिणी ताइवान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के फ्लोरिडा, इंडियाना, उत्तरी कैरोलिना में स्थित प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं में भीषण आग लगने के मामले सामने आए हैं।

2060 तक बढ़कर तिगुना हो जाएगा प्लास्टिक उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक उत्पादन को नाटकीय रूप से कम किए बिना प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना असंभव होगा। इस बारे में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर केवल नौ फीसदी प्लास्टिक कचरे का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। इतना ही नहीं अनुमान है कि आने वाले समय में स्थिति कहीं ज्यादा बदतर हो सकती है क्योंकि 2060 तक प्लास्टिक उत्पादन तिगुना होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ रीसाइक्लिंग में मामूली वृद्धि का अनुमान है।

हालांकि 16 मई, 2023 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, यदि देश और कंपनियां मौजूदा तकनीकों के बेहतर उपयोग के साथ-साथ नीतियों और बाजार में बदलाव करें। तो 2040 इस प्लास्टिक कचरे को 80 फीसदी तक कम किया जा सकता है। ऐसे में ग्रीनपीस ने इस पेरिस वार्ता में, एक महत्वाकांक्षी, कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि की वकालत की है। जो प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करने के साथ-साथ बढ़ते कचरे की रोकथाम में मदद कर सकती है।

तेजी से नष्ट नहीं हो रहे हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने कपड़े, क्या है वजह??

मुंबई। प्लास्टिक प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। हर साल 10 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक वातावरण में प्रवेश करता है, जिसमें से एक करोड़ टन से अधिक हमारे महासागरों में समा जाता है। ये प्लास्टिक हानिकारक सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में इतने छोटे रूप में टूट जाते हैं कि इन्हें समुद्री जीवों द्वारा निगला जा सकता है। फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों और थैलों को प्लास्टिक कचरे के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो हमारे कपड़ों- पॉलिएस्टर, नायलॉन, ऐक्रेलिक और अन्य में बुने जाते हैं ये भी समान रूप से समस्याग्रस्त हैं। हर साल, छह करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक के कपड़ों का उत्पादन होता है, जिसकी काफी मात्रा आखिर में लैंडफिल में जाती है। इस संकट से निपटने का एक तरीका बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग है। इस तरह के प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से गैसों और पानी में टूटने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बाद में लंबे समय तक होने वाले नुकसान के बिना वातावरण में वापस आ जाते हैं।

लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या नष्ट होने की वास्तविकता हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उत्तर रही है। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के नेतृत्व में किए गए नए शोध में पाया गया है कि, पॉलीलैक्टिक एसिड नामक एक लोकप्रिय बायोप्लास्टिक सामग्री पर्यावरण में उतनी जल्दी नष्ट नहीं होती जितनी जल्दी उससे उम्मीद की जाती है। शोधकर्ताओं ने जैव और तेल आधारित प्लास्टिक सामग्री, साथ ही कपास जैसे प्राकृतिक रेशे, तटीय जल और समुद्र तल पर नमूनों के रूप में छोड़ा। समय बीतने के साथ, उन्होंने माइक्रोस्कोप के तहत इन अलग-अलग रेशों की जांच की कि क्या वे टूट रहे हैं। जबकि कपास के रेशे टूटने लगे, पॉलीलैक्टिक एसिड जैसे बायोप्लास्टिक सामग्री सहित सिंथेटिक फाइबर, समुद्र में 400 दिनों तक डूबे रहने के बाद भी टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। कपड़ों से उत्पन्न होने वाला प्लास्टिक प्रदूषण खतरनाक है। कपड़े अक्सर रीसायकल करने योग्य नहीं होते हैं और वे धीरे-धीरे पहनने और घिसने से छोटे प्लास्टिक फाइबर वातावरण में पहुंचते हैं। कपड़ों के रेशे कई रास्तों से हमारे महासागरों तक पहुंच सकते हैं। समुद्र में पहुंचे कपड़े, उदाहरण के लिए, लहरों के चलते या रेत के कणों के साथ घर्षण से टूट जाएंगे। इस प्रक्रिया से कपड़े से रेशे निकल जाते हैं। यहां तक कि केवल हमारे कपड़े पहनने से ही, प्लास्टिक के रेशे वातावरण में मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ आखिर में समुद्र में समा सकते हैं। हमारे कपड़े धोने की प्रक्रिया के दौरान, रेशे उखड़ जाते हैं और हमारी नालियों में बह जाते हैं। — साभार

दुनिया भर में जानलेवा तंबाकू की फसलों को सब्सिडी देना बंद करे सरकारें- डब्ल्यूएचओ

नई दिल्ली। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया है कि वे तंबाकू की खेती को सब्सिडी देना बंद करें। सरकारें अधिक टिकाऊ फसलों पर जोर दे जो लाखों लोगों की भूख मिटा सकती हैं। डब्ल्यूएचओ की एक नई रिपोर्ट, भोजन उगाएं, तंबाकू नहीं , तंबाकू उगाने की बुराइयों और किसानों, लोगों, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरण और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए अधिक टिकाऊ खाद्य फसलों को अपनाने के फायदों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट किसानों को कर्ज के दुष्चक्र में फंसाने के लिए तम्बाकू उद्योग को भी उजागर करती है, इसके आर्थिक फायदों को बढ़ा-चढ़ा कर तम्बाकू उगाने का प्रचार करती है और कृषि मोर्चा समूहों के माध्यम से पैरवी करती है।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि, दुनिया भर में हर साल तंबाकू 80 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार है, फिर भी दुनिया भर में सरकारें तंबाकू के खेतों को बढ़ावा देने के लिए लाखों खर्च करती हैं। उन्होंने कहा, तंबाकू के बजाय भोजन संबंधी फसलें उगाने का चयन करके, हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हैं, और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा में अहम भमिका निभाते हैं।

दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, 120 से अधिक देशों में 30 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपयोग घातक तंबाकू उगाने के लिए किया जा रहा है, यहां तक कि उन देशों में भी जहां लोग भूख से मर रहे हैं। तम्बाकू की खेती स्वयं किसानों को बीमारियां की ओर धकेलती हैं और अनुमान है कि 10 लाख से अधिक बाल श्रमिक तम्बाकू के खेतों में काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा है। डब्ल्यूएचओ में स्वास्थ्य संवर्धन निदेशक डॉ रुएडिगर क्रेच ने कहा कि, तंबाकू न केवल खाद्य असुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि तंबाकू किसानों के स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। किसानों को रासायनिक कीटनाशकों, तंबाकू के धुएं और 50 सिगरेटों में पाए जाने वाले निकोटीन के संपर्क में लाया जाता है, जिससे पुरानी फेफड़ों की बीमारी और निकोटीन विषाक्तता जैसी बीमारियां होती हैं। तंबाकू का बढ़ना एक वैश्विक समस्या है। अब तक ध्यान एशिया और दक्षिण अमेरिका में रहा है, लेकिन नवीनतम आंकड़े दिखाते हैं कि तंबाकू कंपनियां अफ्रीका में भी फैल रही हैं। 2005 के बाद से, पूरे अफ्रीका में तंबाकू की खेती की भूमि में लगभग 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। डब्ल्यूएचओ, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम तंबाकू मुक्त फार्म पहल का समर्थन करते हैं जो केन्या और जाम्बिया में 5,000 से अधिक किसानों को तंबाकू के बजाय स्थायी खाद्य फसलें उगाने में मदद करेगा। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू नियंत्रण में बदलाव लाने वालों को सम्मानित करता है। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में से एक, केन्या की एक महिला किसान, स्प्रीना रोबी चाचा को न केवल तम्बाकू उगाने से लेकर उच्च प्रोटीन बीन्स को अपनाने के लिए, बल्कि एक स्वस्थ समुदाय बनाने के लिए सैकड़ों अन्य किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए भी सम्मानित किया जा रहा है। तम्बाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 182 दलों ने तंबाकू श्रमिकों और उत्पादकों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक महत्वपूर्ण तरीका है कि देश इस दायित्व को पूरा कर सकते हैं, तम्बाकू उगाने के लिए सब्सिडी समाप्त करना और स्वस्थ फसलों का समर्थन करना इसमें शामिल है। डब्ल्यूएचओ की हाल में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि, तम्बाकू के बजाय भोजन उगाने का चयन करके, हम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हैं और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यावरण-प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पौध-रोपण किया

भोपाल मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ सर्वश्री दीपांशु राठौर, मोहित, नीरज और हर्ष राजपूत ने अपने जन्म-दिवस पर भी पौधे लगाए। ट्राय फाउंडेशन के श्री अजय सिसोदिया, सुश्री पूर्वा शर्मा, श्री आयुष और सुश्री नीतू तिवारी ने भी पौध-रोपण किया। विजन डेवलपमेंट फॉर वूमेन वेलफेयर नीड्स सोसायटी की अध्यक्ष सुश्री दिव्या अत्री ने मेरा भोपाल-मेरी जिम्मेदारी अभियान में नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने और पॉलीथीन मुक्त मार्केट के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नागरिकों द्वारा लिए गए इस दायित्व की सराहना की। श्रीमती अंशिता शर्मा, सुश्री वैदेही चौधरी, श्री अमेय शर्मा, श्री प्रभव सोहगौरा भी पौध-रोपण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ दैनिक पत्रिका समाचार पत्र समूह के नेशनल हेड, मार्केटिंग श्री सौरभ भंडारी और राज्य संपादक श्री विजय चौधरी ने भी पौध-रोपण किया। सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी नागरिकों ने हिस्सेदारी की। इसमें सर्वश्री राधेश्याम चौहान, मोहित शर्मा, अंकिता धुर्वे, प्रगति श्रीवास्तव और डोरीलाल धुर्वे शामिल हुए। पौध-रोपण में खातेगांव जिला देवास के श्री योगेश और श्री अर्पित तिवारी भी शामिल हुए।

विश्व पर्यावरण दिवस पर जनभागीदारी का संकल्प, छत्तीसगढ़ में पांच लाख लोग लेंगे शपथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में 01 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिये शपथ का कार्यक्रम रखा गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 01 जून को एक दिन में पांच लाख लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेंगे। प्रदेश में मिशन लाईफ कार्यक्रम के अंतर्गत लाईफ स्टाईल फॉर इन्वायरमेंट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। लाईफ प्लेज के अंतर्गत पूरे राज्य में एक साथ पांच लाख लोगों द्वारा प्लेज लिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता लायी जा सके। एक ही दिन में पांच लाख लोग शपथ लेकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दर्शायेंगे। पूरे प्रदेश में यदि पॉच लाख लोग एक साथ शपथ लेंगे या रायपुर जिले से शपथ की संख्या डेढ़ लाख से पार होगी, तो यह एक विश्व रिकार्ड होगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सभी लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे 01 जून 2023 को पर्यावरण संरक्षण के लिये शपथ लेकर इस महाअभियान में भागीदार बनें। शपथ इस प्रकार है-मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिये अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि अपने परिवार, मित्रों व अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत् रूप से प्रेरित करूंगा।

बक्सर के इस शिक्षक ने पर्यावरण को बचाने के लिए शुरु की मुहिम, लोगों को कर रहे जागरुक

बक्सर. पिछले कुछ वर्षों से जिले में शादी समारोह के दौरान लोगों के बीच एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और इस परंपरा के तहत लोग एक-दूसरे को विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम में पौधों का उपहार दे रहे हैं. यह परंपरा धनसोई के सरकारी शिक्षक विपिन कुमार की प्रेरणा से शुरु हुई है. विपिन कुमार ने पांच वर्ष पूर्व अपनी बहन की शादी में तिलक के दौरान बहन के ससुराल वालों को पौधे उपहार में दिए थे. तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई. आज विपिन विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों के साथ-साथ अपने परिजनों की पूण्य स्मृति में भी लोगों को पौधे लगाने की सीख देते हैं.

विपिन कुमार ने हाल ही में एक विवाह समारोह में 400 पौधों का उपहार सभी बारातियों को दिए थे. उन्होंने ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय में कितना जरूरी है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. जिस तरह से विकास कार्यों के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है. ऐसे में सबको यह सोचना होगा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और ऐसे में विभिन्न अवसरों पर पौधरोपण करना होगा. विपिन कुमार ने बताया कि वह जिस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वहां उपहार स्वरूप लोगों को पौधा वितरित करते हैं और उनसे पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील करते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों समहुता के सिसौंधा निवासी ललन सिंह की पुत्री की शादी समारोह में उपस्थित होने पर उन्होंने लोगों को धरती माता के हरित घर के लिए जागरूक किया और विवाह की एक रस्म जिसमें वधू पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों से भोजन के लिए आग्रह करते हैं. उस वक्त उन्हें एक-एक पौधा प्रदान किया गया और यह संकल्प दिलाया गया कि वह अपने जीवन काल में कम से कम 10 पौधे लगाएंगे. विपिन कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी धार्मिक संस्कारों के मौके पर अपने लोगों की स्मृतियों में पौधा अवश्य लगाएं. यह पौधे आपको छाया के साथ-साथ आपके पूर्वजों की भी याद दिलाता रहेंगे. ऐसा करने से धरती पर जीवन भी बचा रहेगा.

भारत में उच्च घनत्व वाली खेती पर्यावरण के लिए खतरा- कृषि विशेषज्ञ

लखनऊ। उच्च घनत्व वाली खेती से पर्यावरण को होने वाले खतरों के पर चर्चा करते हुए उन्होंने पश्चिम की नकल करने के बजाय खेती के स्थानीय तरीके का उपयोग करने का आग्रह किया। कृषि वैज्ञानिकों को यूरोप और पश्चिम की नक़ल करने के बजाय स्थानीय और देश की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा की मै हैरान हु इस बात से, और ऐसा ही चलता रहा तो एक समय पर ऐसे स्तिथि होगी जिसे हम ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा, अभी भी समय है इसलिए हमे इसे रोकने की जरूरत है।

जैविक कृषि पद्धति से हिमाचल जैसे राज्यों में पारिस्थितिकी और जैव विविधता को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है और खेती में रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए कृषि और बागवानी संस्थानों में और अधिक रिसर्च करने की जरूरत है। जहां तक हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो रिसर्च की बहुत जरूरत है। मैं अब तक उम्मीद कर रहा था कि राज्य के दो विश्वविद्यालय, पालमपुर और सोलन कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च करेंगे, जो व्यावहारिक रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ साबित हो रहे है ।हिमाचल प्रदेश में विश्व की 1 प्रतिशत जैव विविधता ह, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आपको रसायनों के उपयोग को कम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा की हम सरकार की मदद से वैज्ञानिकों से एक नए और विशेष मॉडल को बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। भारत की खेती अब खतरे में है और कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने की आवश्यकता है। न सिर्फ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में खेती पर खतरा बना हुआ है , बल्कि सभी राज्य में किसान अपनी उपज को सड़क पर फेंक रहे हैं और जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और फिर प्याज की कीमतें 25 पैसे प्रति किलोग्राम तक गिरने के कारण मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में किसानों ने भिंडी और लहसुन को नष्ट कर दिया। साथ ही, टमाटर और शिमला मिर्च की कीमते भी कम हो गई है। क्या किसी देश ने कभी इस बात पर विचार किया है कि उत्पाद नष्ट होने के बाद एक किसान कैसे जीता है? क्रेडिट कार्ड पर 20 प्रतिशत टैक्स लगाने को लेकर हंगामा हुआ, किंतु खेती की किसी को कोई चिंता नहीं है। शर्मा ने कहा कि सर्कार को न्यूनतम समर्थन मूल्य(रूस्क) को किसानों का कानूनी अधिकार बनाना चाहिए ।

उन्होंने कहा कि भारत में दो-तीन बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, व्यापार को विनियमित करने की और किसानों को कम से कम उनकी उपज के निवेश की एक सम्मानजनक लागत मिलनी चाहिए। भारत में बाजारों द्वारा कृषि उपज के लिए 900 प्रतिशत से 2000 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। व्यापार को विनियमित करने की आवश्यकता है और अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू वृक्षारोपण-संचालित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। देविंदर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सेब के आयात पर शुल्क के रूप में 50 प्रतिशत टैक्स लगाया है और हम चाहते हैं कि इसे और बढ़ाया जाए ताकि सस्ते आयातित सेब भारतीय सेबों को प्रभावित न कर सके।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008